मानक विचलन: रोजगार के आंकड़ों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

द हिन्दू

4 फरवरी, 2019

"प्रमुख रोजगार डेटा जारी करने में देरी ने डेटा आधिकारिकता की विश्वसनीयता को कम कर दिया है।"

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पी.सी. मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी का इस्तीफा दिसंबर, 2018 में सार्वज. निक किए जाने वाले रोजगार पर नए डेटा को केंद्र सरकार द्वारा इनकार करने से संबंधित प्रतीत होता हैं। हाल ही में वे अर्थव्यवस्था पर अनावरण किए गए बैक-सीरीज डेटा के बारे में भी अनभिज्ञता से संबंधित हो सकते हैं, जो धीमी दर्ज की गई थी।

सरकार ने पिछले साल नवंबर में नीति आयोग के जरिये जीडीपी-आधारित सीरीज जारी की थी, लेकिन परामर्श प्रक्रिया में एनएससी को शामिल नहीं किया, जो एनएससी सदस्यों के साथ अच्छा नहीं था। इसके अलावा उनका दावा है कि एनएससी से परामर्श किए बगैर ही आर्थिक गणना भी शुरू कर दी गई थी।

यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार के शासन के दौरान विकास और नीति आयोग द्वारा सम्मेलन और आयोग के विचारों को दरकिनार कर इसे जारी किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जुलाई, 2017 से दिसंबर, 2018 के लिए नए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के निष्कर्ष बेरोजगारी के साथ-साथ पांच दशक के सबसे उच्च स्तर पर हैं।

एनएससी की एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे 2006 में स्थापित की गई, यह सत्यापित करना है कि सार्वजनिक डोमेन में शामिल किये जा रहे डेटा विश्वसनीय और पर्याप्त हैं या नहीं। सूचना निर्धारित सरकारों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के तहत एकत्रित और प्रसारित की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी है जो कि साल 1972-73 के बाद से सबसे ज्यादा है। साल 1972-73 से पहले का डाटा तुलना योग्य नहीं है। बेरोजगारी के जिस ताजा आंकड़े को मोदी सरकार ने जारी करने से मना कर दिया था।
6.1 फीसदी बेरोजगारी की दर अपने आप में शायद उतनी चिंता का विषय नहीं है लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि साल 2011-12 में ये दर केवल 2.2 फीसदी थी तो फिर बात अलग हो जाती है। और तो और शहरी इलाकों में 15 से 29 साल के लोगों के बीच बेरोजगारी की दर खासा अधिक है।

शहरों में 15 से 29 साल की उम्र के 18.7 फीसदी पुरुष और 27.2 फीसदी महिलाएं नौकरी की तलाश में हैं। इसी उम्र कि श्रेणी में ग्रामीण इलाकों में 17.4 फीसदी पुरुष और 13.6 फीसदी महिलाएं बेरोजगार हैं।
युवाओं के लिए नौकरी के सृजन के सवाल पर, प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिमंडल का तर्क यह है कि रोजगार प्रचुर मात्र में हैं और कमी विश्वसनीय आंकड़े की हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल का कहना है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।

सरकार हर बार पांच साल का एनएसएसओ डेटा जारी करती है लेकिन आयोग के पास सिर्फ एक साल के आंकड़े उपलब्ध हैं। लिहाजा सरकार का मानना है कि इससे सही तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। वर्ष 2016-17 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के पंचवर्षीय रोजगार सर्वे किए जाने थे। लेकिन वर्ष 2017-18 में यह बदल गया क्योंकि इसकी जगह नया श्रम बल सर्वेक्षण तैयार किया जा रहा था।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लेबर ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए चुनिंदा रोजगार-गहन क्षेत्रों का एक त्रैमासिक सर्वेक्षण, जिसने वास्तविकताओं पर कुछ स्पष्टता प्रदान की, उसका बेवजह मजाक उड़ाया गया। इसके बजाय, औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन से प्रॉक्सी डेटा को रोजगार-सृजन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है जिसे अर्थशास्त्रियों ने गलत बताया है। इसके बावजूद, अरुण जेटली ने अपने पिछले साल के बजट भाषण में, 2018-19 में सात मिलियन औपचारिक नौकरियों का दावा करने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन का हवाला दिया था।

पीएम आर्थिक सलाहकार काउंसिल के प्रमुख बिबेक देबरॉय ने कहा है कि भारत के पास 2011-12 के बाद रोजगार बढ़ाने को लेकर कोई ठोस सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। भारतीय श्रमबल अब भी अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में है। सर्वे में भारत के रोजगार

क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत सही समझ पैदा नहीं करता है।

देबरॉय के मुताबिक, वास्तविक मुद्दा रोजगार की संख्या नहीं बल्कि रोजगार की गुणवत्ता तथा वेतन की दर है। उन्होंने कहा कि सरकार सीमित संख्या में ही रोजगार उपलब्ध कर सकती है, इसलिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन सरकार की नौकरियों से बाहर होना चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने नियमित रोजगार सर्वेक्षणों के आधार पर 2018 में नौकरी के नुकसान को 11 मिलियन तक आंका है। रोजगार से संबंधित आंकड़ों के लिए सरकार का व्यापक दृष्टिकोण इसके विनाशकारी प्रदर्शन का कारण हो सकता है जो अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखलाओं और अनौपचारिक नौकरियों को चोट पहुँचाता है और जिसका प्रभाव सुस्त पड़ा हुआ है। मोदी सरकार को भारत की सांख्यिकीय अखंडता को समाप्त किये बिना बेहतर रास्ते पर चलना चाहिए था।

GS World टीम...

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश में रोजगार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट लीक हुई है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1% के स्तर पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है।
- देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3 फीसदी है।
- 15-29 साल के शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी है। 2011-12 में ये दर 8.1 फीसदी थी।
- 2017-18 में शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी बेरोजगारी है जो 2011-12 में 13.1 फीसदी थी।
- एनएसएसओ सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में

- पिछले सालों की तुलना में अभी देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है और यह कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत थी जो 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज्यादा रही। यहाँ बेरोजगारी दर पुरुषों में 18.7 प्रतिशत और महिलाओं में 27.2 प्रतिशत रही।
- पीएलएफएस एनएसएसओ का पहला सालाना हाउसहोल्ड सर्वे है जिसके लिए जुलाई, 2017 से जून, 2018 के दौरान आंकड़े जुटाए गए थे।
- 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट देखी गई और यह 23.3 फीसदी रही जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 31.2 फीसदी और 2009-10 में 32.6 फीसदी रही।
- पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2011-12 में 79.8 फीसदी था जो 2017-18 में 75.8 फीसदी रह गया। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं श्रम नौकरियों से बाहर हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 13.6 प्रतिशत रही जो 2011-12 में 4.8 प्रतिशत थी।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाओं में 2004-05 से 2011-12 तक बेरोजगारी दर 9.7 प्रतिशत से 15.2 प्रतिशत के बीच रही है। 2017-18 में यह बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई।
- शिक्षित ग्रामीण पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3.5-4.4 प्रतिशत के बीच रही।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत थी जो 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई।

क्या है?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

क्या कहा नीति आयोग ने?

- ऐसा कोई भी डेटा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है।
- सरकार तिमाही डेटा पेश करेगी।
- एनएसएसओ का डेटा पूरी तरह से गलत है।
- नीति आयोग के मुताबिक 7-7.8 मिलियन नौकरियां दी गई है।
- देश को अभी 7 मिलियन नौकरियों की जरूरत है।
- मार्च तक नीति आयोग जारी करेगा रिपोर्ट
- रोजगार को लेकर अभी आंकड़े तैयार हो रहे हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. 1950 में स्थापित भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करता है।
2. यह सरकार सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है।
3. रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाके में बेरोजगारी 5.3 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.8 फीसदी है। जो 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. Consider the follwing statements regarding the National Sample Survey Office (NSSO)

1. It is the largest organisation of India established in 1950, which regularly conducts the socio economic survey of the country.
2. It works under the agies of Ministry of Statistics and Programme implementation.
3. According to the report, rate of unemployment in urban areas was 5.3 percent in 2017-18 whereas in rural areas was 7.8 percent, which is the largest after 1972- 73.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2
(b) 1 and 3
(c) 1, 2 and 3
(d) None of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में NSSO द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में बेरोजगारी के सन्दर्भ में सरकार और NSSO के बीच विरोधाभाषी प्रवृति देखने को मिल रही है। इस सन्दर्भ में रोजगार की स्थिति पर विवेचना करते हुए बेरोजगारी को कम करने हेतु अपना सुझाव दें।

(250 शब्द)

Q. 'Detailed Budget indicates rewards of the fiscal inclusion, tax reform and systematic distribution of subsidy. Do you agree with this statement? Discuss.

(250 Words)

नोट : 2 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed to Excellence